भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2540
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

संसद सदस्यों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सेवाएं

2540. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों को बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में समस्याओं, विशेष रूप से नेटवर्क और डेटा कवरेज के मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली डेटा सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क में सुधार और विस्तार करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन दोनों सार्वजनिक उपक्रमों (बीएसएनएल और एमटीएनएल) के नेटवर्क को एकीकृत करने या उनकी कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए कोई कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए, बीएसएनएल ने अखिल भारतीय स्तर पर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाख 4जी साइटों की खरीद के लिए क्रय आदेश दिया है। 06.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, 61,492 साइटें संस्थापित की जा चुकी हैं और 51,135 4जी साइट ऑन-एयर हैं। इसके अलावा, बीएसएनएल ने एमटीएनएल से दिल्ली में 01.04.2021 से और मुंबई में 01.09.2021 से मोबाइल सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) का काम अपने हाथ में ले लिया है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का और विस्तार करने के लिए, बीएसएनएल 4जी सेचुरेशन स्कीम, सीमा चौकी (बीओपी)/सीमा आसूचना चौकी (बीआईपी), वामपंथी उग्रवाद और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में दूरसंचार अवसंरचना के संवर्धन आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान करने सहित सभी ग्राम पंचायतों में और मांग के आधार पर गांवों में फाइबर के विस्तार के लिए 1.39 लाख करोड़ रु. के परिव्यय के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 04.08.2023 को मंजूरी दी गई है। बीएसएनएल इस स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

*****